(c) Priority III is accorded to demo- bilised personnel of armed forces and physically handicapped tor the purpose of submission by Employment Exchanges for vacancies reported in Central Government offices etc., including Delhi Administration Offices. There is no priority for subm.ssion of SC/ST and widow re-gistrants.

(d) and (e) : The Eighth Plan has em-phasised the role of Employment Exchanges in the promotion of self-employment. In order to provide efficient service to both employers and job seekers, computerisation of employment exchanges has been taken up. The Pusa Employment Exchange has already been computerised and Darya Ganj and R. K. Puram Exchanges are in the process of being computerised.

*193. [Transferred to 17th December, 1992]

कोयला खानों के विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र की सहभागिता

*194. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या कोयला मंत्री 16 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न सं. 129 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए अपनी निजी कोयला खानें विकसित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या सरकार ने विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त ऐसे बड़े संयंत्रों की स्थापनार्थ, जिनमें बड़ी मात्रा में कोयले का उपयोग होता है, निजी क्षेत्र को अपनी स्वयं की कोयला खानों का विकास करने हेतु उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निति की घोषणा कब तक कर दिये जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री और श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन किए जाने के लिए एक विधेयक संसद में पारित किया गया है।

इस बिल में विद्युत उत्पादन के लिए ग्रहीत उपभोग के प्रयोजन के लिए अप्रयुक्त क्षेत्र में कोयले के क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) : इस बिल में कोयला खनन क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को उक्त अंतिम प्रयोगों के लिए, जोकि अधिसू-चित किए जाने हैं, की अनुमति मांगी गई है।

Pension Scheme for Newspaper Employees

*195. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL:

SHRI VITHALRAO MADHAV-RAO JADHAV:

Will the Minister of LABOUR be pleas-ed to state :

(a) whether Government have formu-lated the pension scheme for journalists and non-journalists for implementation w.e.f. April next year;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is the reaction of various newspaper organisations to the proposal ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) :

(a) The Government have not formulated a Pension Scheme exclusively for journalists and non-journalists for implementation with effect from April next year.

(b) and (c) : The questions do not arise.

Land Grabbing in Delhi

*196. SHRI SHIV PRATAP MISHKA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that land grabbing in the Union Territory of Delhi has become widespread by influen-